राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

विषयः– "राजस्थान मिशन 2030 अभियान" की विभिन्न गतिविधियों की टाईम लाईन के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत निवेदन है कि आयोजना (ग्रुप–4) विभाग के पत्र क्रमांक प.4(1)आयो./ग्रुप–4/2023 के क्रम में निवेदन है कि राजस्थान मिशन 2030 अभियान की टाईम लाईन में आवंटित स्कूलों/कॉलोजो में लेख एवं भाषण प्रतियोगिता के क्रम में सूचना एवं जनसर्म्पक विभाग द्वारा संदर्भ सामग्री संलग्न है।

राज्य सरकार की उपलब्धियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी सूचना एवं जनसर्म्पक विभाग की **वेबसाइट DIPR. Rajasthan.gov.in** भी पर उपलब्ध है।

संलग्न :– संदर्भ सामग्री

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
राजस्थान, जयपुर

1. **प्रमुख शासन सचिव, उच्चशिक्षा राजस्थान, जयपुर**
2. **सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान, जयपुर**

यू.ओ.नोट क्रमांक 93-94 दिनांक 29/08/2023

राजस्थान ने पिछले पांच वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की है–

1. राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक–2023 तथा गिग वर्कर्स के लिए राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) विधेयक पारित करने वाला देश में पहला राज्य है।

2. स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 25 लाख रू तक के कैशलेस उपचार की सुविधा। निशुल्क जांच, दवा, और इलाज की सुविधा।

3. **मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना** में परिवार में एक से अधिक सदस्य की मृत्यु की स्थिति में परिवार को 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा।

4. **मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना** में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी एवं आईपीडी सुविधाएं पूर्णत निःशुल्क।

5. 27 जिला चिकित्सालय, 67 उप जिला अस्पताल, 10 सेटेलाइट अस्पताल स्वीकृत। 268 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया गया। 610 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत एवं नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत। 1742 नये स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोले जाने की स्वीकृति जारी।

6. राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 16,816 बैड (शैय्या वृद्धि) की स्वीकृति जारी।

7. 43 **ट्रोमा सेन्टरों** की स्थापना की गई।

8. सुशासन को गति देने के लिए प्रदेश में 17 **नये जिले** बनाने से प्रदेश में कुल 50 जिले। प्रदेश में 3 **नये संभाग**–बांसवाड़ा, पाली एवं सीकर बने।

9. वर्तमान सरकार के गठन से जुलाई 2023 तक 13 अतिरिक्त जिला कलक्टर, 1 सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (AC&EM), 35 उपखण्ड, 85 तहसील, 129 उप–तहसीलें, 32 भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त कार्यालय एवं 1130 नवीन पटवार मण्डल सृजित किये गये। 1295 राजस्व ग्राम सृजित किए गए।

10. अपने खेत पर आवास बनाने वाले कृषकों को भी आवास ऋण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत का व्याज अनुदान।

11. ग्रामीण क्षेत्र में **Non-Farming Sector** जैसे हस्तशिल्प, लघु उद्योग. कताई–बुनाई, रंगाई–छपाई एवं दुकान इत्यादि हेतु एक लाख 50 हजार परिवारो को सहकारी बैंको के माध्यम से 3 हजार करोड रूपये के ब्याज मुक्त ऋण का वितरण किया जायेगा।

12. 386 तहसीलों के भू–अभिलेख को आमजन के उपयोग हेतु ऑनलाइन किया।

13. समस्त ऑनलाईन तहसीलों में **स्वतः नामान्तरकरण** प्रक्रिया प्रारम्भ।

14. अब तक करीब 1 लाख 66 हजार सरकारी पदों पर नियुक्तियां और 1 लाख 68 हजार से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन।

15. प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल आदि की रोकथाम के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक–2023 पारित जिसमें उम्रकैद तक की सजा के प्रावधान।

16. प्रदेश सरकार द्वारा अपने पैसों से जालोर, प्रतापगढ़ और राजसमंद में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय, 33 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज।

17. महंगाई से राहत देने के लिए **'बचत राहत–बढ़त'** की थीम पर आधारित वर्ष 2023–24 की बजट की घोषणाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए महंगाई राहत कैंप का आयोजन।

18. जन–आधार डेटाबेस का उपयोग करके पूर्ण पारदर्शी तरीके से राज्य की 10 महत्वपूर्ण योजनाओं के पात्र परिवारों की पहचान कर, उन्हें इन योजनाओं का लाभ देने के लिये पूरे राज्य में **मंहगाई राहत कैंप** आयोजित। इन कैम्प्स में 1.83 करोड़ परिवारों परिवारों का मौके पर रजिस्ट्रेशन कर 7.69 करोड़ मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड प्रदान की गई।

19. प्रतिमाह न्यूनतम 1 हजार रूपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 500 रूपए में घरेलू गैस सिलेंडर, हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख का दुर्घटना बीमा, प्रतिमाह निःशुल्क 100 यूनिट घरेलू एवं 2 हजार यूनिट कृषि बिजली, निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, गांवों और शहरों में 125 दिन के रोजगार के साथ ही दुधारू पशुओं का बीमा।

20. बीपीएल एवं उज्जवला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग के परिवारों को सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2023 से 500 रु में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है, सिलेण्डर खरीद पर 50 लाख 66 हजार से अधिक लाभार्थियों के खाते में लगभग 215 करोड़ रु की राशि हस्तांतरित कर लाभान्वित किया गया।

21. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 93 लाख 50 हजार लाभार्थियों को 39 हजार 147 करोड़ रु की पेंशन राशि वितरित।

22. कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक–बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी का प्रावधान

23. एक करोड़ से अधिक एनएफएसए परिवारों को प्रतिमाह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट। इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट में एक–एक किलो चना दाल, चीनी व आयोडाइज्ड नमक, एक लीटर सोयाबीन रिफाइण्ड खाद्य तेल, 100–100 ग्राम मिर्च पाडडर व धनिया पाउडर तथा 50 ग्राम हल्दी पाउडर निःशुल्क दिया जा रहा है। दिनांक 21.08.2023 तक 22.25 लाख से अधिक अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण लाभार्थियों का किया जा चुका है।

24. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) परिवारों के साथ–साथ जिन नॉन–एनएफएसए परिवारों को कोविड में आर्थिक सहायता मिली थी, उन्हें भी अन्नपूर्णा राशन किट योजना में निःशुल्क राशन किट उपलब्ध कराए जाएंगें।

25. उन कृषकों को, जो ऋणग्रस्ता के कारण संकट में है, राहत प्रदान करने के लिए न्यायनिर्णयन के पश्चात पंचाट पारित करने और सुलह और बातचीत के माध्यम से ऐसे कृषकों की शिकायतों के निवारण के लिए सिफारिश करने हेतु राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक–2023 पारित।

26. अलग से कृषि बजट प्रस्तुत करने की अनुकरणीय पहल, कृषक कल्याण कोष की राशि बढ़ाकर 7 हजार 500 करोड़ रु की गई।

27. कृषकों के खेतों पर 65.5 लाख मीटर की तारबंदी पर कृषकों को रूपये 69.11 करोड़ का अनुदान प्रदान।

28. तारबंदी योजना में 1 लाख किसानों को 4 करोड़ मीटर लंबाई में तारबंदी के लिए 444 करोड़ रु का अनुदान का लक्ष्य। वर्ष 2023–24 के दौरान में 56,593 आवेदन पत्रो की प्रशासनिक स्वीकृति।

29. लम्पी रोग से दुधारू गोवंश पशुओं की मृत्यु पर पशुपालकों को 40 हजार रु की सहायता उपलब्ध करवाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य। प्रथम फेज में 42 हजार 162 मृत दुधारू गोवंश के लिए 168 करोड़ 64 लाख 80 हजार रु पशुपालकों के खाते में हस्तांतरित किए गए। द्वितीय चरण में 1213 पशुपालको के 1265 मृत गौवंश के 5 करोड़ 06 लाख की राशि हस्तान्तरित की गई।

30. 14,000 मेगावॉट (सोलर रूफटॉप सहित) **सौर ऊर्जा संयंत्र** एवं 894 मेगावॉट पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित।

31. 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य। 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ। सभी उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री एवं फ्यूल सरचार्ज समाप्त।

32. मिनिमम गारंटी विधेयक पारित, जिससे प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हर वर्ष 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी स्वतः हो जाएगी।

33. अब तक सिलिकोसिस से पीड़ित 13 हजार 595 पीड़ितों एवं आश्रित परिवारों को 410 करोड़ रु से ज्यादा की आर्थिक सहायता।

34. वर्ष 2021 से अब तक विशेष योग्यजन को 5 हजार 734 स्कूटियां वितरित की गई हैं।

35. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 182.78 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए, 17.60 लाख कार्य पूर्ण किए गए तथा 42991 करोड़ रूपए व्यय किए गए।

36. **मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत** में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को अब राजस्थान में स्थायी रूप से 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार तथा कथौड़ी सहरिया एवं विशेष योग्यजन को भी स्थायी रूप से 100 दिवस के स्थान पर 200 दिवस का रोजगार।

37. **राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका)** द्वारा 23,379 ग्रामों में, 2. 12 लाख स्वयं सहायता समूह, 25 हजार से अधिक ग्राम संगठन, 845 संकुल स्तरीय संगठन का गठन कर 42 लाख ग्रामीण परिवार लाभान्वित किये गये।

38. स्वयं सहायता समूहों को रूपये 733 करोड़ की राशि **आजीविका सवर्धन** हेतु उपलब्ध करायी गयी।

39. **स्वयं सहायता समूहों** को रूपये 3592 करोड़ का बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया।

40. **प्रशासन गांवों के संग अभियान में** राजस्व विभाग द्वारा मुख्य कार्यो यथा राजस्व अभिलेखों/खातों का शुद्धिकरण के 23.19 लाख, आपसी सहमति से खाता विभाजन के 2.23 लाख, नामांतकरण के 24 लाख, सीमाज्ञान के 3.83 लाख, सरकारी/चारागाह/विभागीय भूमियों के अतिक्रमण से संबंधित प्रकरण के 72,325 तथा रास्तों संबंधित के 1.46 लाख प्रकरणों में निस्तारण की कार्यवाही की गई।

41. पंचायती राज विभाग द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में 12.72 लाख निर्मित पुराने भवनों का नियमितिकरण, 55,051 पात्र व्यक्तियों के 2003 तक के कब्जो का नियमितिकरण कर पट्टे जारी किये गये तथा 26,655 पात्र व्यक्तियों को रियायती दर पर भूखंड आवंटन एवं 37,129 बी.पी.एल परिवारों को निःशुल्क भूखण्ड आवंटन किया गया।

42. 995 इंदिरा रसोइयों के माध्यम से 8 रु में शुद्ध व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2023–24 के बजट में इंदिरा रसोई का ग्रामीण कस्बों में भी विस्तार करते हुए इनकी संख्या बढ़ाकर दो हजार करने की घोषणा की गई है।

43. **इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना** में **125 दिवस का रोजगार।**

44. **इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना–2021** में शहरी क्षेत्र के 2.39 लाख स्ट्रीट वेण्डर्स, बेरोजगारों को रोजगार के लिए बैंको के द्वारा 664 करोड़ रूपये ऋण वितरित।

45. **प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021** में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा लगभग 8 लाख 72 हजार पट्टे जारी कर एवं विभिन्न सेवाओं (भवन निर्माण, नाम हस्तान्तरण, उपविभाजन/पुर्नगठन, खांचा भूमि व लीज प्रकरण आदि) के 23 लाख 33 हजार प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

46. **पर्यटन विकास कोष** की राशि बढ़ाकर 1 हजार 500 करोड़ रुपये।

47. **पर्यटन व हॉस्पिटेलिटी सेक्टर** को अब **उद्योग** के दर्जे के पूर्ण परिलाभ देय। अब इस सेक्टर पर भी Industrial norms के अनुसार ही Government tariff व Levies देय होंगे। 897 इकाइयों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी।

48. **विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय** के विकास के लिये कोष का गठन।

49. **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास कोष** की राशि को 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2023–24 में एक हजार करोड़ रुपये।

50. अल्पसंख्यक विकास कोष की राशि को बढ़ाते हुए वर्ष 2023–24 में 200 करोड रूपये।

51. प्रदेश में लोक कला को जीवित रखने के साथ–साथ लोक कलाकारों को सम्बल प्रदान करने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपये राशि का **लोक कलाकार कल्याण कोष**–कोष के अंतर्गत **मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना** लागू।

52. सफाई कर्मचारियों के विकास के लिए गठित **'वाल्मीकि कोष'** की राशि 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2023–24 में 100 करोड़ रुपये।

53. **अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग विकास कोषों** की राशि बढ़ाते हुए वर्ष 2023–24 में 200–200 करोड़ रूपये।

54. **मिरासी समुदाय** के विकास के लिए 20 करोड़ रूपये का कोष गठित।

55. हिन्दू, जैन, सिख व मुस्लिम तीर्थ स्थलों के विकास हेतु 89 करोड़ 33 लाख रु का धार्मिक पर्यटन सर्किट स्वीकृत कर विकास कार्य करवाये जा रहे हैं।

56. धार्मिक पर्यटन स्थलों पर संरक्षण, सौंदर्यीकरण एवं विकास हेतु 124 करोड़ रु के कार्य स्वीकृत किए गए।

57. इन्वेस्ट राजस्थान सम्मिट से पूर्व आयोजित रोड शो/ इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत रूपये 12.53 लाख करोड़ रूपये के 4195 MoU/LoI हस्ताक्षरित। 2,174 एमओयू/एलओआई धरातल पर उतर चुके हैं अथवा क्रियान्वयन के उन्नत चरणों में हैं।

58. **राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम 2019** – 8,631, लघु श्रेणी के 6,217 एवं मध्यम श्रेणी के 3,501 का पंजीयन। 5 वर्ष के लिये स्वीकृतियों एवं निरीक्षणों से मुक्त।

59. **राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना**–2022 के अंतर्गत 82,450 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्तावों के 2893 पात्रता प्रमाण पत्र जारी।

60. राज्य में परम्परागत शिल्पकलाओं के विकास, प्रोत्साहन और हस्तशिल्पियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से राज्य की प्रथम **हस्तशिल्प नीति–2022** जारी।

61. **डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना–2022** – अनुसूचित जाति/ अनूसूचित जनजाति वर्ग के 286 आवेदकों/ उद्यमियों को रूपये 86 करोड़ के ऋण वितरित।

62. राज्य के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के उत्थान के लिए **एमएसएमई नीति–2022**

63. **मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना** – 30,152 आवेदकों को ऋण स्वीकृत कर 26,246 आवेदकों को 5712 करोड़ रूपये का ऋण वितरित।

64. **मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना**न्तर्गत कार्ड धारक बुनकर को 1 लाख रूपये एवं आर्टीजन/हस्तशिल्पियों को 3 लाख रूपये तक के ऋण पर लगने वाले ब्याज का शत–प्रतिशत पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा।

65. 176 **औद्योगिक क्षेत्र** स्थापित करने की घोषणा। अब तक 49 औद्योगिक क्षेत्र उद्यमियों के लिये भूखण्ड आवंटन हेतु खोले गये। 68 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु 2,915 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी। रीको द्वारा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को 5,463 भूखण्ड आवंटित।

66. **स्टार्टअप नीति, 2022** जारी।

67. **अल्प आय वर्ग की महिलाओं**, कामगार, विभिन्न वंचित वर्ग यथा– हस्तशिल्पी, केशकला व माटी कला कारीगर एवं घुमन्तू आदि को स्वरोजगार के लिए '**विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना**'

68. **वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना** में नये तीर्थ स्थल अयोध्या–उत्तरप्रदेश, सम्मेद शिखर, वैद्यनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग–झारखण्ड, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक–महाराष्ट्र एवं श्रवणबेलगोला– कर्नाटक भी शामिल किये गये।

69. **वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा** में 1,09,808 रेल यात्रा एवं 16,388 हवाई यात्रा (कुल 1,26,196 वरिष्ठ नागरिकों) को तीर्थ यात्रा करवायी गयी।

70. वर्ष 2019–20 से राज्य के 4082 वरिष्ठ नागरिकों को **पशुपतिनाथ मंदिर** दर्शनार्थ काठमांडू (नेपाल) हवाई यात्रा करवायी गयी।

71. ऑपरेशन 'सुदर्शन चक्र' संचालित कर हिस्ट्रीशीटर्स, माफियाओं, आदतन अपराधियों सहित करीब 40 हजार असामाजिक तत्वों की धरपकड़ की गई है।

72. प्रदेश में संगठित रूप से कार्यरत विभिन्न माफियाओं यथा–Land माफिया, बजरी माफिया एवं Loan माफिया इत्यादि पर कड़ी एवं त्वरित कार्रवाई करने के लिए SOG के अन्तर्गत **Special Task Force** के गठन की स्वीकृति जारी।

73. शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए **Raj-Kaj software** को प्रयोग में लाने एवं ई–फाइल सिस्टम लागू।

74. **महिला शक्ति आत्मरक्षा केन्द्रों** के माध्यम से 11 लाख से अधिक महिलाओं व बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

75. **सुरक्षा सखी योजना** के तहत लगभग 22 हजार सुरक्षा सखी सदस्यों का चयन किया गया है।

76. **जल जीवन मिशन** के अन्तर्गत अब तक राशि रूपये **71,038 करोड़ की स्वीकृति** जारी की जा चुकी है, जिससे **11,167** एकल जलप्रदाय परियोजनाएं एवं 134 वृह्द परियोजनाएं शामिल हैं। इन स्वीकृत योजनाओं से लगभग **95 लाख परिवारों को घरेलू जल संबंधों** द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी। अब तक कुल **31.93** लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है।

77. प्रदेश के 13 जिलों यथा–अजमेर, अलवर, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, झालावाड, भरतपुर, दौसा, जयपुर एवं टोंक के लिए **पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना** (ERCP) जीवनदायिनी साबित होगी, इसीलिए अपने वित्तीय संसाधनों से

ERCP का कार्य निरन्तर जारी रखेंगे। अभी तक 1284 करोड़ रुपये व्यय कर नवनेरा बैराज एवं ईसरदा बांध के कार्य प्रगतिरत है।

78. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना(ERCP) के कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से कराने की दृष्टि से **पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम** (ERCP Corporation) का गठन किया गया है। निगम द्वारा रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज एवं नवनैरा–गलवा–बीसलपुर–ईसरदा लिंक परियोजना के कार्यो हेतु राशि रूपये 15113 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 12.04.2023 को जारी की जाकर निविदाएं आमंत्रित कर ली गई है।

79. 33 हजार 440 करोड़ रूपये व्यय कर प्रदेश में 66 हजार 237 किमी सड़कों का निर्माण एवं विकास कार्य किया गया। 49,062 करोड़ रूपये लागत के **77,773 कि. मी.** लम्बाई में सड़कों के 20,119 विकास कार्य स्वीकृत किये गये है।

80. 3 हजार 606 **महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय** अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित किए जिनमें 6 लाख 21 हजार से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं।

81. राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत प्रतिदिन पाउडर मिल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है।

82. राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत 66 लाख 46 हजार से अधिक विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफार्म।

83. **Right to Education Act (RTE)** के अंतर्गत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक में निःशुल्क अध्ययनरत बालिकाओं एवं बालकों को कक्षा 09–12 तक में भी निःशुल्क अध्ययन की सुविधा

84. राज्य में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए **309 नवीन महाविद्यालय** खोले जिनमें 132 कन्या महाविद्यालय हैं।

85. राज्य में कुल 63 कृषि महाविद्यालय संचालित इनमें से 51 **नवीन कृषि महाविद्यालय** गत 4 वर्ष 6 माह में खोले गये।

86. 21 नवीन राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय खोले गये। इससे 33 जिलों में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित।

87. **राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना** – वर्ष 2023–24 में विद्यार्थियों की संख्या 200 से बढ़ाकर 500।

88. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सिद्धातों, विचारों एवं दर्शन का जन–जन तक पहुॅचाने के उद्देश्य से नवाचार के रूप में प्रदेश में **शान्ति एवं अहिंसा विभाग** की स्थापना।

89. युवाओं में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों एवं शांति व अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए **महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशियल साइंसेज विधेयक**, 2023 पारित किया गया।

90. **इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना** के प्रथम चरण में लगभग 40 लाख महिला लाभार्थियों को स्मार्टफोन एवं डाटा सिम का वितरण करने हेतु 10 अगस्त 2023 से शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अगले चरण में करीब 1 करोड़ स्मार्टफोन देने हेतु गारंटी कार्ड का वितरण प्रारम्भ। इन्हें दिखाकर महिलाएं स्मार्टफोन निःशुल्क ले सकेंगी।

91. महिलाओं को रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में दी जाने वाली किराये में छूट को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया।

92. **राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलम्पिक खेल–2023** में लगभग 58 लाख 51 हजार खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।

93. 1 जनवरी, 2004 और इसके पश्चात् नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए भी **पूर्व पेंशन योजना (OPS)** लागू। साथ ही, प्रदेश के सभी बोर्ड, निगम एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में पुरानी पेंशन योजना लागू।

94. राज्य में **CGHS** की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु **RGHS** (Rajasthan Government Health Scheme) योजना।

95. सबसे ज्यादा दूध उत्पादन में देश में पहला स्थान।

96. जयपुर में देश का सबसे बड़ा मेडिकल टॉवर बन रहा है।

97. अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश में पहला स्थान।

98. आर्थिक विकास दर में 8.19 प्रतिशत की बढ़ोतरी

99. प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में 30वें स्थान से उठकर 21वें स्थान पर पहुंचा।

100. 1 करोड़ 51 लाख महिलाओं तथा किशोरियों को **सैनेटरी नैपकिन**।

101. महिलाओं एवं बालिकाओं के विरूद्ध छेड़छाड़/असम्मानजनक व्यवहार आदि अपराधों की रोकथाम हेतु **महिला गश्ती दल निर्भया स्क्वॉड।**

102. जोबनेर–जयपुर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय के साथ ही **नवीन पशुपालन विश्वविद्यालय** (Veterinary University) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

103. 9 नवीन **राजकीय पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय** खोले जा रहे है।

104. 13 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों को **बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत** किया गया है।

105. 49 पशु चिकित्सालय को **प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत** किया गया।

106. 198 पशु औषधालयों को **पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत**, 234 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को **पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत** किया गया। वर्ष 2023–24 में 92 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को **पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत** किया जायेगा।

107. प्रदेश की पशु चिकित्सा संस्था विहिन 1637 ग्राम पंचायतों में **नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र** खोले गये। वर्ष 2023–24 में 507 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जायेंगे।

108. 381 नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले गये, 2027 प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय में, 5916 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया।

109. 1 जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 10 नवीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय/नवीन सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय, 35 नवीन पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, 476 पुलिस थाने निरीक्षक स्तर में क्रमोन्नत, 77 नवसृजित थाने, 49 पुलिस चौकी थानों में क्रमोन्नत, 117 पुलिस चौकी नवसृजित तथा सभी जिलों में साइबर पुलिस थाने स्थापित किये गये।

110. वर्ष 2019 में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के तहत 57 **पंचायत समितियों** तथा 1456 नवीन **ग्राम पंचायतों** का सृजन किया गया। वर्ष 2022 में 3 नवीन पंचायत समितियों का सृजन किया गया।

111. वर्ष 2022–23 में जयपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं भरतपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाकर 19,366 आशार्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान किये गये। बजट घोषणा 2023–2024 में 100 **मेगा जॉब फेयर** आयोजित करने की अनुपालना में 24 जलाई, 2023 तक कुल 13 मेगा जॉब फेयर (अजमेर, बांसवाडा, सवाई माधोपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, नागौर, दौसा कोटा, राजसंमद, सीकर, श्रीगंगानगर, जसलमेर, एवं जालौर) का आयोजन किया जाकर 32,130 आशार्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान किये गये। इस प्रकार अब तक कुल 17 मेगा जॉब फेयर आयोजित कर कुल 51,496 युवाओं का प्राथमिक चयन किया गया।